meet the situation will be made by the Central Team which is currently visiting the State.

(e) Government has released Rs. 21·00 crores representing the full annual Central contribution to the Calamity Relief Fund of Punjab for the year 1993-94. It has also been decided to release in advance Central share of two quarterly instalments of Calamity Relief Fund for the year 1994-95 amounting to Rs. 10·50 crores.

कानपुर शहर के विकास के लिये विश्व बैंक की सहायता

*97. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से कानपुर में शहर विकास परियोजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में गत वर्ष का क्या लक्ष्य था और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं । "नगर विकास" राज्य का विषय है और ऐसी नगर विकास योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना धन से अथवा बाह्य सहायता से बनाई और चलाई जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश में इस समय विश्व बैंक सहायता से एक नगर विकास योजना चल रही है । कानपुर भी 15 लाभ-ग्राही नगरों में शामिल है । 1992-93 के लिए कानपुर के लिये 9.33 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से .75 करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

परियोजना की शुरूआत से 1992-93 के अन्त तक, कानपुर के लिये संचयी लक्ष्य 38.3 करोड़ रुपये का था, जिसमें से 33.22 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

रायचूर मध्य प्रदेश में बारूका बांध परियोजना

*98. **श्री अजीत जोगी** :

चौधरी हरि सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रायचूर की बारूका बांध (अपर पेरी) परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को भेजी गई थी ;

(ग) इस परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बारूका बांध 916.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की संशोधित महानदी जलाशय परियोजना का घटक है । संशोधित परियोजना रिपोर्ट फरवरी 1990 में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी ।

(घ) मूल्यांकन अभिकरणों ने जांच के बाद सिंचाई आयोजना, जल विज्ञान, लागत अनुमानों पर राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी हैं । परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी इन टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है ।